

कित प्रश्न संख्या 1969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना किसी विदेशी सहयोग के 8 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये नई दिल्ली और मेरठ की जिन फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनके नाम और पते क्या हैं तथा ये प्रस्ताव किस किस तारीख को प्राप्त हुए थे ।

(ख) क्या बदनी स्थित परीक्षण केन्द्र में प्रोटो टाइप ट्रैक्टरों का परीक्षण किया गया है और क्या सरकार ने उसके बाद उक्त प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दो फर्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम और पते ये हैं : भैसर्स सैलगयोकार इंजीनियर्स प्रा० लि०, डी०-9 साउथ एक्स-टेंसन, भाग-2 नई दिल्ली तथा मेसर्स डेल्टा इंजीनियरिंग क० प्रा० लि०, पोस्ट बाक्स नं० 35, मेरठ । विनियोजन, निर्माण कार्यक्रम आदि के औपचारिक विस्तृत विवरण सहित किसी भी पार्टी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । भारतीय जानकारी से ट्रैक्टर निर्माण करने की सूचना नई दिल्ली की फर्म से 17 अप्रैल, 1969 को तथा मेरठ की फर्म 28 मार्च 1969 को प्राप्त हुई थी ।

(ख) तथा (ग) : प्रोटो टाइप ट्रैक्टरी का परीक्षण अभी तक बुंचनी स्थित परीक्षण केन्द्र में नहीं किया गया है ।

Loss of Railway goods from Railway wagons

*765. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a very

large quantity of Railway goods is lost through wagon breaking, pilferage and theft every year;

(b) whether any estimate has been made by his Ministry about the extent of loss on this account in the different Railways;

(c) whether it is also a fact that the Railway employees are scared to take action against the criminals because adequate protection is not given to them and the local Police do not respond favourably in tracking down the criminals; and

(d) if so, what steps Government have taken to liaison with the State Governments to ensure that the Police help at the State level is spontaneous in tracking down criminals and the loss on this account is minimised?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) Yes, Sir. The claims bill in the recent years has gone up, which is the only available index in determining the quantity of railway goods lost through wagon breaking, pilferage and theft.

(b) Yes, Sir. A statement regarding the loss (claims—compensation) on this account on the various zonal railways is placed on the table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1830[69].

(c) No, Sir. Railway Protection Force staff who are responsible to provide better protection and security to the railway property, have been taking suitable action against the criminals found committing thefts. They have also been engaged in several encounters with gangs of armed criminals and have been successful in safeguarding the railway property from being looted. Local Police have also been responding favourably in tracking down the criminals.

(d) Close liaison at all levels is maintained with the State Police for

enlisting their help in minimising the loss on account of pilferages, and the following steps are *inter-alia* being taken:—

- (1) The goods trains passing through the affected sections and carrying valuable commodities are provided with Railway Protection Force escorts.
- (2) Big and important yards where the incidence of theft and pilferage is reported to be high are patrolled by armed parties and by dog squads.
- (3) Plain-clothed staff is deployed to collect crime intelligence for tracking down culprits.

वकीलों की फीस

*766. श्री विभूति मिश्र : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे तथा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के वकीलों और अधिवक्ताओं की फीस हजारों और लाखों रुपयों तक चली गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारी रकम खर्च करके न्याय प्राप्त करना लोगों के सामर्थ्य से बाहर की बात है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) सरकार के पास इस विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि विभिन्न न्यायालयों में प्लीडर और एडवोकेट कितनी फीस लेते हैं। फीस कितनी ली जाती है यह

कई बातों पर निर्भर है जैसे वकील किस कोर्ट का है और उस का अनुभव कितना है, उसकी सेवाओं की मांग कितनी है तथा इसी प्रकार की अन्य बातें। किन्तु यह सच है कि बड़े बड़े तथा उच्च कोर्ट के वकील भारी भारी फीसें लेते हैं।

(ख) जी नहीं। कुशल वकील सामान्य और युक्तियुक्त फीसों पर मिल जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

चुनावों के दौरान मद्य निषेध

*767. श्री राम गोपाल शालवाले : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि चुनावों के दौरान शराब की खपत बढ़ जाती है और इस प्रकार स्वस्थ मतदान में बाधा पड़ती है ;

(ख) क्या चुनावों के दौरान मद्य-निषेध लागू करने का विचार है : और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) निर्वाचन आयोग को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निर्वाचन के दौरान शराब की खपत बढ़ जाती है जिससे अबाध तथा निष्पक्ष मतदान पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) और (ग) आयोग ने, सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से, अगामी और निर्वाचनों में मतदान के दिन तथा उसके ठीक पहले वाले दो दिन शराब की बिक्री तथा उपभोग पर प्रतिरोध लगाने की सिफारिश की है।